17 फरवरी, 2022 करेंट अफेयर्स

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization - WHO) दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (एसईएआर) ने 'तंबाकू छोड़ो ऐप (Quit Tobacco App)' लॉन्च किया है। यह एप्लिकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है।
- ऐप को WHO-SEAR की क्षेत्रीय निदेशक, डॉ पूनम खेत्रपाल सिंह (Poonam Khetrapal Singh) ने WHO के साल भर चलने वाले 'कमिट टू क्विट (Commit to quit)' अभियान के दौरान लॉन्च किया, जो WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है।
- डब्ल्यूएचओ द्वारा इस तरह का पहला, और सभी प्रकार के तंबाकू को लक्षित करने वाला पहला ऐप, उपयोगकर्ताओं को ट्रिगर्स की पहचान करने, उनके लक्ष्य निर्धारित करने, क्रेविंग को प्रबंधित करने और तंबाकू छोड़ने के लिए ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
- तंबाकू दुनिया में रोके जा सकने वाली मौतों का प्रमुख कारण है और हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। यह डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 1.6

मिलियन लोगों के जीवन का दावा करता है जो तंबाकू उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है।

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड**
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना: 7 अप्रैल 1948**
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक: टेड्रोस एडनॉम**

2. बिहार में खादी के ब्रांड एंबेसडर होंगे मनोज तिवारी

- भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एंबेसडर होंगे। राज्य के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussain) ने घोषणा की कि वह बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए "ब्रांड एंबेसडर" होंगे।
- मनोज तिवारी खादी के कपड़े के उपयोग को बढ़ावा देंगे, जिसे महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बनाया था। तिवारी, जिन्होंने "गैंग्स ऑफ वासेपुर" चार्टबस्टर "जिया हो बिहार के लाला" सहित असंख्य फुट-टैपिंग नंबरों को अपनी आवाज दी है।
- **बिहार राज्यपाल: फागू चौहान**
- **बिहार राजधानी: पटना**

- **बिहार के मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार**

3. यस बैंक ने शुरू किया 'एग्री इन्फिनिटी' कार्यक्रम

- निजी क्षेत्र के ऋणदाता, यस बैंक (Yes Bank) ने इस क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्तपोषण समाधान के लिए एक 'एग्री इन्फिनिटी (Agri Infinity)' कार्यक्रम शुरू किया है।
- खाद्य और कृषि मूल्य श्रृंखला में वित्तीय नवाचारों पर काम कर रहे एग्री-फिनटेक स्टार्ट-अप इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं और डिजिटल समाधान के लिए यस बैंक के साथ काम कर सकते हैं।
- इस पहल के माध्यम से, स्टार्टअप्स के एक चुनिंदा समूह को न केवल अनुभवी बैंकरों द्वारा अनुभवात्मक सह-विकास के लिए परामर्श प्राप्त होगा, बल्कि यस बैंक के डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी, नए समाधानों का संचालन करने के लिए सहयोगी अवसर और धन उगाहने की सलाह भी मिलेगी।
- उत्पत्ति, किसान ऑन-बोर्डिंग, किसान केवाईसी, क्रेडिट स्कोरिंग, जोखिम मूल्यांकन, निगरानी और शमन, संवितरण और वसूली समाधान और नकद प्रबंधन प्रणाली में शामिल लोग आवेदन कर सकते हैं।
- **यस बैंक की स्थापना: 2004**
- **यस बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र**

- **यस बैंक के सीईओ: प्रशांत कुमार**
- **यस बैंक टैगलाइन: एक्सपीरियंस अवर एक्स्पर्टीज़**

4. जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति घटकर 12.96% हुई

- भारत की थोक महंगाई जनवरी में घटकर 12.96% हो गई, जो पिछले महीने में 13.56% थी। हाल के महीनों में थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index - WPI) आधारित मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है।
- यह नवंबर 2021 में 14.87% से गिरकर दिसंबर 2021 में 13.56% और जनवरी 2022 में 12.96% हो गया। हालांकि, मुद्रास्फीति अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और आर्थिक नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है।
- जनवरी 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, खाद्य पदार्थों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।
- थोक खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी महीने के दौरान सख्त हुई। WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर दिसंबर 2021 में 9.24% से मामूली रूप से बढ़कर जनवरी 2022 में 9.55% हो गई।
- दिसंबर 2021 की तुलना में जनवरी 2022 में खनिजों की कीमतें 11.08% बढ़ीं और गैर-खाद्य वस्तुएं 0.37% महंगी हो गईं।

5. जियो प्लेटफॉर्म्स ने यूएस-आधारित टेक स्टार्टअप TWO Platforms में 25% हिस्सेदारी खरीदी

- जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) ने US-आधारित डीप-टेक स्टार्टअप कंपनी टू प्लेटफॉर्म्स (TWO Platforms) में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी ली है। टू प्लेटफॉर्म एक आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी है जो इंटरैक्टिव और इमर्सिव एआई अनुभवों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- दोनों कंपनियों ने नई तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने और एआई, मेटावर्स और मिश्रित वास्तविकताओं जैसी विघटनकारी तकनीकों का निर्माण करने के लिए हाथ मिलाया है। टू प्लेटफॉर्म रीयल-टाइम AI वॉयस और वीडियो कॉल, डिजिटल ह्यूमन, इमर्सिव स्पेस और लाइफलाइक गेमिंग को सक्षम बनाता है।
- यह अपनी इंटरएक्टिव एआई प्रौद्योगिकियों को पहले उपभोक्ता अनुप्रयोगों के बाद मनोरंजन और गेमिंग के साथ-साथ खुदरा, सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित उद्यम समाधान लाने की योजना बना रहा है। मंच की स्थापना भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री (Pranav Mistry) ने की थी।

6. सिडबी ने 'वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन' कार्यक्रम शुरू किया

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India - SIDBI) ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए 'वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन (Waste to Wealth Creation)' कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शोपीस बनाएगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा।
- इस कार्यक्रम के तहत, बाद में, इन महिलाओं से अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक बनने की उम्मीद की जाती है। यह सिडबी के मिशन स्वावलंबन का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य कारीगरों को टिकाऊ बनने में सहायता करना है।
- **सिडबी की स्थापना: 2 अप्रैल 1990**
- **सिडबी मुख्यालय: लखनऊ**
- **सिडबी के अध्यक्ष और एमडी: शिवसुब्रमण्यम रमण**

7. सेबी ने अध्यक्ष और एमडी/सीईओ की भूमिका को अलग करने की आवश्यकता को स्वैच्छिक बनाया

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India - Sebi) बोर्ड ने पहले 'अनिवार्य (mandatory)' के खिलाफ 'स्वैच्छिक (voluntary)' के रूप में अध्यक्ष और एमडी / सीईओ की भूमिकाओं को अलग करने का प्रावधान करने का निर्णय लिया है।
- मार्केट रेगुलेटर ने जून 2017 में उदय कोटक (Uday Kotak) के तहत कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद लिस्टेड कंपनियों के कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को और बढ़ाने के लिए सिफारिशें लेना था।
- समिति की सिफारिशों में सूचीबद्ध कंपनियों के अध्यक्ष और एमडी/सीईओ की भूमिकाओं को अलग करना था। प्रबंधन के अधिक प्रभावी और वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण को सक्षम करके एक बेहतर और अधिक संतुलित शासन संरचना प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था।
- सेबी बोर्ड ने मार्च 2018 में अपनी बैठक में शीर्ष 500-सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बाद में अनुपालन की समय सीमा जनवरी 2020 में दो साल के लिए बढ़ा दी गई थी।
- **सेबी की स्थापना: 12 अप्रैल 1992**

- **सेबी मुख्यालय: मुंबई**
- **सेबी अध्यक्ष: अजय त्यागी**

8. केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने चौथी भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह-अध्यक्षता की

- चौथी भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता (India-Australia Energy Dialogue) की सह-अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, आरके सिंह (RK Singh) और ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री एंगस टेलर (Angus Taylor) ने की।
- ऊर्जा परिवर्तन वार्ता और दोनों ऊर्जा मंत्रियों में चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भंडारण, ईवी, महत्वपूर्ण खनिज, खनन आदि पर ध्यान देने के साथ अपने-अपने देशों में ऊर्जा संक्रमण गतिविधियां।
- विकासशील देशों के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत द्वारा जलवायु वित्त की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। दोनों देशों ने नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने और वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के लिए उनकी तैनाती को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए एक आशय पत्र (Letter of Intent - LoI) पर हस्ताक्षर किए।

9. भारत की G20 प्रेसीडेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने G20 सचिवालय का गठन किया

- भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 शिखर सम्मेलन 2023 (18वें संस्करण) में भारत में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए सरकार ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है।
- G20 सचिवालय को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री: अमित शाह, विदेश मंत्री: एस जयशंकर और G20 शेरपा: पीयूष गोयल।
- G20 सचिवालय भारत के आगामी G20 प्रेसीडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। 2021 में, G20 शिखर सम्मेलन रोम, इटली में आयोजित किया गया था। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा जबकि 2023 में यह नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा।

10. TERI का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन शुरू

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (The Energy and Resources Institute's - TERI) वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन भाषण दिया।
- इस अवसर पर डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति श्री लुइस अबिनादर (Luis Abinader), गुयाना के सहकारी गणराज्य के अध्यक्ष डॉ मोहम्मद इरफान अली (Mohamed Irfaan Ali), संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव सुश्री अमीना जे मोहम्मद (Amina J Mohammed) और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) उपस्थित थे।
- डब्ल्यूएसडीएस का 21वां संस्करण 16-18 फरवरी 2022 तक निर्धारित है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय एक लचीला ग्रह की ओर: एक सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना (Towards a Resilient Planet: Ensuring a Sustainable and Equitable Future) है।
- प्रधान मंत्री ने याद किया कि उनके 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और सतत विकास उनके लिए मुख्य फोकस क्षेत्र रहे हैं, पहले गुजरात में और अब राष्ट्रीय स्तर पर।

- प्रधानमंत्री ने सात वर्षों से चल रही एलईडी बल्ब वितरण योजना के बारे में बताया, जिससे प्रति वर्ष 220 अरब यूनिट बिजली और 180 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने में मदद मिली है।
- उन्होंने टेरी जैसे अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों को हरित हाइड्रोजन की क्षमता का एहसास करने के लिए स्केलेबल समाधान के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया।

11. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने "डार्कथॉन-2022" का आयोजन किया

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau - NCB) डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए "डार्कथॉन (Darkathon)-2022" का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजा जा सके।
- एजेंसी ने हाल ही में ड्रग पेडलर्स के तीन समूहों को तोड़ दिया जो नेटवर्क पर काम कर रहे थे जो कि एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं की गुमनामी को सक्षम बनाता है।
- प्रथम विजेता को 2.50 लाख रुपये, उपविजेता को 2 लाख रुपये और तीसरे विजेता को 1.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चौथे और पांचवें स्थान के लिए

सांत्वना पुरस्कार 25,000 रुपये है। ऑनलाइन पंजीकरण 31 मार्च तक https://ncb.cyberchallenge.in के माध्यम से जारी रहेगा।

- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक: सत्य नारायण प्रधान**
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय: नई दिल्ली**
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना: 1986**

12. सामाजिक न्याय मंत्रालय ने डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार (Virendra Kumar) ने नई दिल्ली के डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में DNTs के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना (SEED) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में SEED योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है।
- SEED का उद्देश्य डी-नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी-नोमैडिक आदिवासी समुदायों (DNT/NT/SNT) का कल्याण है, जो सबसे ज्यादा उपेक्षित, हाशिए और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं।

इस योजना में निम्नलिखित चार घटक होंगे:

- डीएनटी/एनटी/एसएनटी उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें।
- डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
- डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदाय संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना।
- डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के सदस्यों को घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

13. 'ह्यूमेन: हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबंडनड पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया

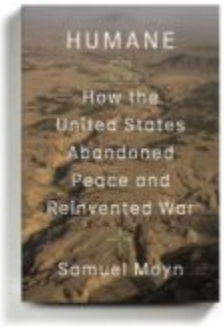

- सैमुअल मोयन (Samuel Moyn) द्वारा लिखित "ह्यूमेन: हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबंडनड पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर (Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War)" नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। सैमुअल मोयन येल लॉ स्कूल (Yale Law School) में न्यायशास्त्र के प्रोफेसर और येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं।

- यह उत्तेजक पुस्तक वियतनाम युद्ध (1955-1975), कोरियाई युद्ध (1950-1953), द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) आदि सहित अतीत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए गए अंतहीन युद्धों के बारे में तर्क देती है और यह विकास प्रगति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

- पुस्तक युद्ध लड़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की रणनीति पर प्रकाश डालती है और कैसे सशस्त्र युद्ध को विवादों को हल करने के लिए एक अपूर्ण उपकरण से आधुनिक स्थिति के एक अभिन्न अंग में बदल दिया गया था।

14. बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का निधन

- महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी (Sandhya Mukherjee) का 90 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका पूरा नाम गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय (Geetashree Sandhya Mukhopadhyay) था। उन्हें हाल ही में केंद्र सरकार से जनवरी 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

- उन्होंने कहा कि पद्मश्री कोई पुरस्कार नहीं है जो उनके जैसे दिग्गज को दिया जाना चाहिए। उसे स्वीकार करना उनके लिए अशोभनीय होगा। उनका जन्म 1931 में कोलकाता में हुआ था, संध्या मुखर्जी ने अपना पहला गाना 1948 में हिंदी फिल्म अंजान गढ़ के लिए रिकॉर्ड किया था।

- संगीत राय चंद बोरल (Rai Chand Boral) ने दिया था। उन्होंने एस डी बर्मन, रोशन और मदन मोहन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के निर्देशन में गाया था।

15. LAHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए "कुनस्योम योजना" शुरू की

- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (Ladakh Autonomous Hill Development Council - LAHDC), लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना (Kunsnyoms scheme) शुरू की है। कुनस्योम का अर्थ सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है।
- नई योजना के तहत लेह हिल काउंसिल जरूरतमंद लोगों को 90 फीसदी सब्सिडी पर सहायक उपकरण, तकनीक मुहैया करा रही है।
- नई योजना का शुभारंभ करते हुए, एलएएचडीसी लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद और अध्यक्ष, श्री ताशी ग्यालसन (Tashi Gyalson) और उनके कार्यकारी पार्षदों ने 28 ट्राई स्कूटर, बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर, चलने में सहायक उपकरण और व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के लिए आवश्यक अन्य सहायता प्रदान की हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, बजट के पर्याप्त आवंटन के साथ आर्थिक रूप से सशक्त, लद्दाख में पहाड़ी परिषदें कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का उपयोग कर रही हैं।
- **लद्दाख (UT) उपराज्यपाल: राधा कृष्ण माथुर**